distillation unit will be ready and it cannot be utilised because the subsequent processes of the kerosene treating unit and the coker unit will not be ready for another year. Is this true or wrong? If it is substantially true, who and what is responsible for this faulty planning?

SHRI K. D. MALAVIYA: So far as my information goes, it is not substantially true. There will be a time gap between the crude distillation unit and the kerosene treating unit. There may be a few months imbalance because, as I said from the beginning, there have been some difficulties in the planning and availability of proper type of men, but I do not think there is going to be a gap of one year. There may be gap of a few months as I am able to see just now. It will be the effort of the Government and myself to see that this time gap is shortened as far as possible.

Electrification of Railway Tracks to Conserve Foreign Exchange

*307. SHRI NITIRAJ SINGH CHAUDHARY: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) whether the Railways propose electrification of Railway tracks in a big way to conserve foreign exchange and also foreign dependence on supply of crude; and

(b) if so, the broad outlines of the scheme to be implemented?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI BUTA SINGH): (a) The pace of electrification on the Indian Railways would depend upon the availability of resources and the densities of traffic. Keeping in view the existing constraints of resources and economics of electrification, it appears unlikely that electrification would be undertaken at a scale which would be substantially more than hitherto.

(b) The sections likely to be taken up for electrification are still under consideration of the Government

श्री नीतिराज सिंह चौधरी : अध्यक्ष जी, वर्ल्ड एनर्जी कांफेंस जो 1974 में हुई थी, उसने संसार भर के कूड के रिजर्व के बारे में सर्वेक्षण कराया था। संसार में जितना कूड है वह 30 से 50 वर्ष में समाप्त हो जायगा। स्टेस्टीकल इंस्टीच्यूट के डा० कीर्त्य पारिख ने इस देश में जितना प्रमाणित कोयला है, उसके आधार पर अनुमान लगाया था। उससे मालूम हुआ कि यह कोयला दो सौ वर्ष तक चलेगा। इस देश में थोरियम और यूरेनियम भी हैं। इन सब के होते हुए जब हम विद्युत उत्पन्न कर सकते हैं और उससे रेलों को चला सकते है तो विदेशों को कूड के लिए लगातार रुपया क्यों दिया जा रहा है, क्यों नहीं रेलों का विद्युतीकरण किया जाता है?

श्री बूटा सिंह : रेलों के विद्युतीकरण के बारे जो कहा गया, यह बात सही है कि विद्युतीकरण से बहुत किफायत होगी, गाड़ियों की रफ्तार बढ़ेगी और माल ढोने में भी फायदा होगा। परन्तु इसके रास्ते में जो सबसे बड़ी चीज आती है वह है पैसे की उपलब्धि। पैसे की कमी की वजह से पांचवें, छट्ठे और सातवें प्लान में जितना विद्युतीकरण करने के बारे में हमने सोचा था, उस गति से, उस रफ्तार से वह नहीं हो पा रहा है। यदि आप आज्ञा दें तो मैं आपसे नम्र निवेदन करना चाहता हूं कि पैसा बहुत कम मिल रहा है। फिफ्थ फाइव इयर प्लान में हमने 120 करोड़ रुपया मांगा था लेकिन पिछले तीन वर्षों में 60 करोड़ रुपया मिला है जो 50 प्रतिशत बनता है?

परन्तु इसी समय में विद्युतीकरण की जो कीमत है, उसकी जो लागत है वह और भी ज्यादा बढ़ चुकी है। इसी कारण से हम अपनी गति को कायम नहीं रख सके हैं।

श्री नीतिराज सिंह चौधरी : आपने बताया है कि किन सैक्शंज का विद्युतीकरण किया जाए यह विचाराधीन है। कलकत्ता से दिल्ली का बहुत कुछ विद्युतीकरण हो गया है। कलकत्ता से नागपुर का हुआ है। बम्बई से भोसावल का हुआ है। इस सब को देखते हुए क्या यह आशा की जाए कि यह जो बीच का हिस्सा है भोसावल से इलाहाबाद, भोसावल से नागपुर और दिल्ली मद्रास और जो रह गया है इनके काम को पहले ले लिया जाएगा और एक ऐसी जगह केन्द्र बनाया जाएगा जिससे सारा काम एक सिलसिले से बढ़ता जा सके ?

श्री बूटा सिंह : माननीय सदस्य ने जो सुझाव दिया है इसको हम जरूर ध्यान में रखेंगे। परन्तु किन सैक्शंज पर काम हुआ है, उनके नाम अगर आप आज्ञा दें तो मैं पढ़ दूं। काम अच्छा हो रहा है, यह मैं कह सकता हूं।

श्री डी० एन० तिवारी विद्युतीकरण में कुछ इम्बैलेंस है। बड़ी लाइनों में हो रहा है लेकिन छोटी लाइनों में अभी उसका नामोनिशान नहीं है। जो लाइन लखनऊ से अनम जाती है या एन ई आर है या एन एफ आर है यहां कहीं विद्युतीकरण नहीं हुआ है। इन सब को कब टेक अप किया जाएगा और क्या कभी देश में बैलेंस लाने की कोशिश की जाएगी ?

श्री बूटा सिंह हमारा प्रयास यह है कि विद्युतीकरण सब से पहले ब्राड गेज लाइनों पर ही हो क्योंकि उन्हीं के माध्यम से ज्यादा तर काम होता है। साथ ही हम यह भी चाहते हैं कि जो मीटर गेज है या जो नैरो गेज है उनको ब्राड गेज कर दें ताकि एक यूनिफार्म गेज हो जाए।

SHRI P. VENKATASUBBAIAH: May I know whether the programme of electrification of the railway track between Madras and Vijayawada is going on as per schedule? I also want to know whether sufficient funds are available and when it will be completed?

SHRI BUTA SINGH. The work between Vijaywada and Madras section is going on according to schedule and will be completed within the stipulated period provided the funds are available.

MR. SPEAKER: What period?

SHRI BUTA SINGH. The funds have already been allocated and the work is progressing.

SHRI P. VENKATASUBBAIAH: It is most unfair. How do you say like that?

MR. SPEAKER: Can you throw some light on this?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI MOHD. SHAFI QURESHI). On this section, we have taken over the work and is expected to be completed by 1979-80.

SHRI INDRAJIT GUPTA: I want to know which are the important electrification projects which are at present in hand on which construction is proceeding? May I also know whether it is the policy of the Railway Ministry to retrench those railway electrification workers who have worked on this project, as soon as the project is completed? I also want to know whether these workers who have been working for years together—for example, I have in mind the Pans-cum-Haldia line on which the work is completed—are being retrenched in a large number? I also want to know whether the policy is to retrench them or to deploy them on other projects which are also being taken up elsewhere?

SHRI BUTA SINGH: As far as the first part of the question is concerned,

we have taken in hand five projects from Kriandul-Waltair, Tundla-Delhi, Madras-Vijayawada, Madras-Trivelore and Bhusaval-Drug. So far as the question of retrenchment of those casual workers who are employed in a particular project is concerned, it is in the nature of a casual workers' job itself and after the project is completed, they have to go home. But we take sufficient care and give priority to these workers wherever the work is available; and this is a continuous process; it is plan after plan that the electrification work has to go. Sufficient care will be taken to see that the workers are not unnecessarily retrenched.

श्री ओंकार लाल बेरवा : तेल के ऊपर हमारी कितनी विदेशी मुद्रा खर्च होती है और डीजलीकरण और विद्युतीकरण में कितना और क्या अन्तर है ?

श्री बूटा सिंह : यह तो बताया जा सकता है कि कितना तेल खर्च करते है। इसका विवरण अगर चाहे तो एक अलग से प्रश्न कर दें।

श्री ओंकार लाल बेरवा : विदेशी मुद्रा कितनी खर्च होती है यह तो बता ही सकते हैं।

श्री हरि किशोर सिंह : श्री डी० एन० तिवारी के प्रश्न के उत्तर में अभी मंत्री जी ने बताया है कि छोटी लाइनों को हम ब्राड गेज में परिवर्तित कर रहे हैं। इस वास्ते हम उन लाइनों का विद्युतीकरण नहीं कर रहे है। मैं जानना चाहता हू कि विद्युतीकरण के रास्ते में क्या मीटर गेज और नैरो गेज कोई टेक्नीकल बाधा डालती है ?

मैं यह भी जानना चाहता हूं कि टुंडला से दिल्ली तक लाइन कब तक कम्प्लीट हो जाएगी, कब तक इसका विद्युतीकरण हो जाएगा ?

श्री बूटा सिंह : प्राथमिकता देने का जहां तक प्रश्न है यह तो आप जानते ही हैं अच्छी तरह से कि कुछ बातों के आधार पर ही प्राथमिकताएं दी जाती हैं और डेंसिटी आफ ट्रेफिक को भी देखा जाता है। जहां तक टुंडला और दिल्ली का जो सैक्शन है उसका ताल्लुक है इसी वर्ष के अन्त तक इसके पूरा हो जाने की आशा है।

Requirement and Production of Hormones

*311. SHRI NANUBHAI N. PATEL: Will the Minister of CHEMICALS AND FERTILIZERS be pleased to state:

(a) what is the country's requirement of Hormones and what are the hormones produced in the country;

(b) what steps Government have taken to encourage firms having less than 26 per cent foreign equity to produce hormones; and

(c) when it is expected to break the monopoly of foreign firms in this field?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI C. P. MAJHI): (a) Data regarding country's requirement of steroids and Hormones and their production is contained in Annexure I to Chapter II of the Report of the Committee on Drugs and Pharmaceutical Industry. A copy of this Report was Slaid on the Table of the House on 8-5 75.

(b) and (c). Two Indian companies are licensed to produce different types of hormones and steroids in the country. One more company has been given a letter of intent for some items falling under this category of products. Assistance is also being accorded to Indian Sector for procurement of necessary technology from abroad. The technology for the manufacture of hormones and steroids is of highly sophisticated nature. The Indian sector of the Industry is however given preference in approval of manufacturing schemes.